राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार, 19 जून 2026
वर्ष 14, अंक 70, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

लखनऊ मेट्रो में अब एक कार्ड से पूरे देश में सफर...03

सलमान खान की वजह से हुई गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में शूटर ने उगला सच..04

## Telegram नया डार्क वेब, अपराधियों और आतंकवादियों का अड्डा कोर्ट में केंद्र ने क्या-क्या कहा

21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले भारत में टेलीग्राम सेवाओं को कुछ समय के लिए रोकने के केंद्र के फैसले के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने हृश्वश्वञ्ज री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर बैन को लेकर केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि क्या हम 150 मिलियन लोगों के अधिकारों को सिर्फ़ इसलिए कैसे रोक सकते हैं क्योंकि कुछ नागरिक परीक्षा दे रहे हैं? क्या किसी परीक्षा के लिए 15 करोड़ यूजर्स की आवाज दबाई जा सकती है? कोर्ट ने टेलीग्राम की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता से पूछा कि आपकी बात समझने के लिए आप यह कहकर कि यह कोई इमरजेंसी नहीं है. यहां पावर के नेचर पर सवाल उठा रहे हैं. दूसरा आप कह रहे हैं कि जानकारी ब्लॉक की जा सकती है, पूरे प्लेटफॉर्म को नहीं. टेलीग्राम और केंद्र सरकार की लंबी दलीलें सुनने के बाद जस्टिस तेजस करिया ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत जारी ब्लॉकिंग ऑर्डर को चुनौती देने वाली प्लेटफॉर्म की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ब्लॉकिंग ऑर्डर सही प्रक्रिया का पालन करके पास किया गया था और बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने इसका रिव्यू किया था. मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों के पास परीक्षा में गड़बड़ी के संबंध में प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल का संकेत देने वाला काफी मटीरियल है और तर्क दिया कि कोर्ट को इसमें शामिल बड़े पब्लिक इंटरेस्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.



### ऑर्डर अपने आप में पूरा था: अटॉर्नी जनरल

अटॉर्नी जनरल ने सरकार के स्टैंड का समर्थन करते हुए कहा कि ऑर्डर 'अपने आप में पूरा' था और इसमें दखल देने की ज़रूरत वाले कारणों को ठीक से दर्ज किया गया था. उन्होंने तर्क दिया कि प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत के आधार पर टेलीग्राम की चुनौती मामले के तथ्यों को लेकर गलत थी. हमारे जैसा देश रोकथाम की कार्रवाई नहीं कर सकता तो हम कहां जाएं? वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार को और नुकसान होने से पहले कार्रवाई करनी चाहिए. सुनवाई के दौरान केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि आतंकवाद, साइबर क्राइम और ड्रग तस्करी के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है. इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम नया डार्क वेब बन रहा है, जो क्रिमिनल्स को जोड़ रहा है और उनके गैर-कानूनी कामों को बढ़ावा दे रहा है. केंद्र सरकार ने ये बातें टेलीग्राम की उस पिटीशन का विरोध करते हुए फाइल किए गए एफिडेविट में कहीं, जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) री-एग्जाम से पहले 22 जून तक भारत में इसके ऑपरेशन पर बैन लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी.

### टेलीग्राम नया डार्क वेब बन गया

काउंटर एफिडेविट में लिखा है कि टेलीग्राम नया डार्क वेब बन गया है, जो थ्रेट एक्टर्स को जोड़ रहा है. क्रिमिनल्स ने डीप वेब लिंक्स के जरिए डार्क वेब फोरम्स से जुड़ने वाले चैनलों पर लिंक पोस्ट करने के लिए तेज़ी से टेलीग्राम को अपनाया है, जिससे अधिकारियों के लिए क्रिमिनल्स को ट्रैक करना और उनके बारे में पता लगाना मुश्किल हो गया है. दरअसल, केंद्र सरकार का यह फैसला इस चिंता पर आधारित था कि टेलीग्राम का इस्तेमाल हृश्वश्वञ्ज-त्र 2026 पेपर लीक में शामिल संगठित धोखाधड़ी नेटवर्क द्वारा किया गया था, जिसके कारण मूल रूप से मई 2026 में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (रूश्वढ्ढञ्जङ्घ) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत एक निर्देश जारी किया, जिसमें 22 जून तक भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म तक पहुंच को प्रतिबंधित किया गया.

### अधिकारियों ने क्या तर्क दिए?

एक अन्य आदेश ने प्लेटफॉर्म को पहले से पोस्ट किए गए संदेशों के लिए संदेश-संपादन सुविधा को 30 जून तक अक्षम करने का निर्देश दिया. सरकार ने 21 जून को होने वाली पुनः परीक्षा की रक्षा के लिए इस उपाय को आवश्यक बताया. अधिकारियों ने तर्क दिया कि टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल लीक या फर्जी प्रश्न पत्रों को वितरित करने, धोखाधड़ी करने और मंच की संपादन सुविधा के माध्यम से संदेश टाइमस्टैम्प में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा था. कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसने गैर-कानूनी हृश्वश्वञ्ज कंटेंट से जुड़े 900 से ज़्यादा लिंक हटा दिए हैं और उल्लंघन की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टूल्स और मैनुअल मॉडरेशन का इस्तेमाल किया है. केंद्र ने अब टेलीग्राम की याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें ऐप पर टेम्परारी बैन को सही ठहराया गया है.

### 'नीट माफिया' नाम का टेलीग्राम चैनल

दूसरी दलीलों के अलावा केंद्र सरकार ने कहा है कि 'नीट माफिया' नाम का एक टेलीग्राम चैनल पहचाना गया था, जिसके पिछली बार चेक करने पर लगभग 18,617 सब्सक्राइबर थे. एफिडेविट के मुताबिक, यह चैनल कथित हृश्वश्वञ्ज परीक्षा के पेपर लीक, एडवांस बुकिंग अरेंजमेंट, पेमेंट कलेक्शन मैकेनिज्म और परीक्षा से जुड़े मटीरियल की उपलब्धता के बारे में आश्वासन से जुड़ा कंटेंट एक्टिव रूप से फैला रहा था. केंद्र के काउंटर एफिडेविट में आगे कहा गया है, उस चैनल का स्केल ही दिखाता है कि टेलीग्राम एक ही समय में हजारों यूज़र्स तक गैर-कानूनी परीक्षा से जुड़ा कंटेंट बड़े पैमाने पर फैलाने में मदद कर सकता है. केंद्र सरकार के मुताबिक, टेलीग्राम का यूनिक टेक्निकल आर्किटेक्चर, जो पूरी तरह से क्लाउड-बेस्ड है, बड़ी मात्रा में कंटेंट के ट्रांसमिशन की इजाज़त देता है.

## CM योगी को भा गई बिठूर की माटी से बनी ये खास 'गुल्लक', देखते ही बोले- बेहद खूबसूरत, इसे आगे बढ़ाएं

उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर अब अपनी पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक के अनूठे संगम के लिए चर्चा में है. गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे के दौरान जिला प्रशासन ने उन्हें एक बेहद विशेष उपहार भेंट किया. कानपुर के जिलाधिकारी (डीएम) जितेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को बिठूर की मिट्टी से बनी और आईआईटी कानपुर की तकनीक से निखरी एक बेहद आकर्षक 'गुल्लक' भेंट की. यह गुल्लक केवल एक उपहार नहीं, बल्कि स्थानीय रोजगार और इनोवेशन का एक बड़ा प्रतीक बनकर उभरी है. इस सराहनीय पहल के पीछे आईआईटी कानपुर के 'रणजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र' का विजन और बिठूर के स्थानीय कुम्हारों की कड़ी मेहनत है. संस्थान के विशेषज्ञ बिठूर की पारंपरिक माटी कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं. पारंपरिक और साधारण दिखने वाली मिट्टी की गुल्लकों को अब एक नया और आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है.



### आकर्षित करने वाली गुल्लक

बच्चों को आकर्षित करने के लिए इन्हें विभिन्न कार्टून किरदारों, पशु-पक्षियों और समकालीन डिजाइनों में ढाला जा रहा है. साथ ही, इन पर बेहतरीन और सुरक्षित रंगों का उपयोग किया जा रहा है. आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ स्थानीय कुम्हारों को सिर्फ डिजाइन ही नहीं, बल्कि आधुनिक निर्माण तकनीकों, उत्पादों की मजबूती (गुणवत्ता नियंत्रण) और सुरक्षित पैकेजिंग का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि ये उत्पाद बिना टूटे दूर-दराज के बाजारों तक पहुंच सकें.CM योगी को भेंट किया गया अनोखा उपहार इस पहल का एक मुख्य सामाजिक उद्देश्य बच्चों में बचपन से ही अपनी संस्कृति से जुड़कर बचत करने की आदत को प्रोत्साहित करना है. ?सीएम के दौरे के दौरान डीएम द्वारा यही गुल्लक भेंट की गई. इस अनोखे उपहार को देखकर सीएम योगी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए. उन्होंने डीएम से कहा कि वाकई यह अच्छी पहल है और इसको और ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सीएम के लिए यह उपहार कला, संस्कृति और आधुनिकता का संगम है.

### अब बुके से नहीं होगा स्वागत

गुल्लक सदियों से हमारे घरों की पहचान रही है, इसमें ऐतिहासिक बिठूर की मिट्टी का प्रयोग किया गया है और आईआईटी कानपुर जैसी संस्था में इसको बनाया गया है. इसके अलावा, ?बिठूर के कुम्हारों के इस हुनर को बड़े पैमाने पर बाजार देने और प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए कानपुर जिला प्रशासन ने एक अनुकरणीय फैसला लिया है. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार, अब जिले के सभी सरकारी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथियों का स्वागत बुके (गुलदस्ते) या प्लास्टिक के स्मृति चिन्ह देकर नहीं, बल्कि बिठूर की मिट्टी से बनी इन्हीं खूबसूरत गुल्लकों को भेंट करके किया जाएगा.??मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रशासन और आईआईटी कानपुर के इस अभिनव प्रयास की सराहना की है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह 'कानपुर मॉडल' प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा.

## राम मंदिर में दान चोरी का कैसे हुआ खुलासा? नृपेंद्र मिश्रा ने दिया जवाब, साथ ही बोले- ये आखिरी वार्निंग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में दान घोटाले के आरोपों पर बात की. उन्होंने इस मामले के हर पहलू पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि दान चोरी की ये घटना सबसे पहले कैसे पकड़ में आई. इसके साथ ही उन्होंने निगरानी व्यवस्था पर भी बात की. उन्होने कहा, मुझे ये सूचना मिली है कि कुछ धनराशि किसी कक्ष के पास टॉयलेट है, वहां मिली. इसके बाद ये जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मिली तो वो आधे घंटे में वहां पहुंचे. फिर जांच शुरू हुई. उन्होंने सहयोगियों से मंत्रणा करके यह सही समझा कि इसकी जांच के लिए राज्य सरकार एसआईटी गठित करे. निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, दान को लेकर सभी की जिम्मेदारियां तय है. बैंक की क्या जिम्मेदारी है. यह भी लिखा है कि ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी है. यहां तक कि ये है कि दान की काउंटिंग में शामिल लोगों के कपड़ों में जेब ना हो. चंपत राय को लेकर क्या धारणा बनाई जानी चाहिए? वो इसमें



शामिल हैं या वो निष्कलंक हैं? इन सवालों पर उन्होंने कहा, वो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं. उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया है.

### चंपत राय पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा हुआ है तो वो इसमें शामिल हैं. वो प्रबंधन के मुखिया हैं. मुखिया होने के कारण लोग आज कहने की स्थिति में हैं लेकिन ऐसा नहीं है. मुख्य कारण ये है कि पूरे मंदिर परिसर में निगरानी की जो व्यवस्था है वह या तो है नहीं, अगर है तो बहुत लचर है.

### मंदिर परिसर में 800 सीसीटीवी कैमरे

नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, मंदिर परिसम में करीब 800 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. कंट्रोल रूम है, जिसे पुलिस देखती है लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है. अगर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी लगे हैं और कहा ये जा रहा है कि सीसीटीवी से ही पता लगा है कि ऐसा हुआ है तो सही बात ये है कि सीसीटीवी की निगरानी प्रभावित हुई है.

### जमीन खरीद पर क्या बोले नृपेंद्र मिश्रा?

टीवी9 के सवाल- चंपत राय ने कई गुना ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदी? इस पर उन्होंने कहा, जो जमीन खरीदी गई थी, वो पहली वार्निंग थी. जिस सावधानी से करना चाहिए थी वो नहीं हुई. कुछ जमीनें जो जरूरी थीं वो हमें लेनी थीं. अयोध्या में एक कठिनाई है कि वहां ज्यादातर जमीन नजूल की है. नतीजा क्या है कि नेगोशिएट तो मैं आपसे करूं लेकिन रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है. अब ट्रस्ट के सामने का विकल्प क्या है. कुछ कठिनाइयां थी लेकिन मैं कहूंगा कि उस समय नऔर ट्रांसपैरेंट होता तो और अच्छा था. अब जो ये सेकेंड वार्निंग है. वो अंतिम है. जमीन की खरीद में सावधानी नहीं बरती गई. खरीद की प्रक्रिया और पारदर्शी होना चाहिए था.

## संक्षिप्त ख़बरें

### 50000 की भैंस बनी 'VIP', सुरक्षा में तैनात हुई इस राज्य की पुलिस; रातभर पहरा क्यों दे रही?

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुथलपट्टू मंडल के थिम्मिरेड्डीपल्ली गांव में एक मेले के दौरान भैंस की बलि को अधिकारियों ने रोक दिया. गांव वाले 50 हजार रुपये में खरीदी गई भैंस की बलि देने ही वाले थे, तभी तीन युवकों ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय में शिकायत दर्ज करा दी. जिला प्रशासन को सूचना दी गई और पुलिस ने रात भर निगरानी रखकर पशु बलि को रख दिया. यह पूरा इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. चित्तूर जिले में एक भैंस को पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता पड़ गई. पुथलपट्टू मंडल के थिम्मिरेड्डीपल्लील गांव में मेले में आयोजन किया था, जिसमें शामिल होने के दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे. गांव के बुजुर्गों ने विद्वानों से परामर्श करके गांव में अम्मावरी जतारा आयोजित करने का समय तय किया था. मेले के हिस्से के रूप में एक भैंस की बलि देने का निर्णय लिया गया और गांव वालों ने मिलकर 50,000 रुपये में भैंस खरीदी.

#### ऐसे टली पशु बलि

हालांकि, इसकी जानकारी मिलने पर गांव के तीन युवकों ने पशु बलि का विरोध किया और भैंस की तस्वीरों के साथ केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने पर केंद्रीय अधिकारियों ने जिला प्रशासन को सूचित किया. जिला कलेक्टर के आदेशानुसार, पुथलपट्टू तहसीलदार उदय सतीश गांव पहुंचे और पशु बलि रोकने के लिए कदम उठाए. साथ ही, जिला एसपी तुषार दुदी के आदेश पर पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की.

## UP को मिलेगी नई रफ्तार! लखनऊ-कानपुर के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल, CM योगी ने किया बड़ा ऐलान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बुनियादी ढांचे को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का बड़ा एलान किया है. गुरुवार को उन्नाव में एक भव्य जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली-मेरठ की तर्ज पर अब लखनऊ और कानपुर को जोड़ने के लिए उन्नाव होते हुए रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही, नवगठित स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के विकास को रफ्तार देने के लिए एक विशाल आउटर रिंग रोड भी बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जून को उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 101 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब उन्नाव को लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) में शामिल कर लिया गया है. लखनऊ का विकास अब सिर्फ हजरतगंज जैसे चुनिंदा इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका विस्तार उन्नाव और कानपुर तक होगा.




### 6 जिलों से जुड़ेगा आउटर रिंग रोड

क्षेत्र में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक मेगा कनेक्टिविटी प्लान पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रस्तावित आउटर रिंग रोड उत्तर प्रदेश के छह प्रमुख जिलों को आपस में जोड़ेगा, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली शामिल होंगे. इस रिंग रोड के बनने से यह पूरा क्षेत्र एक बड़े विकास क्लस्टर के रूप में उभरेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे. इसके अतिरिक्त, उन्नाव और कानपुर के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए गंगा नदी पर दो नए पुलों के निर्माण के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है.

### 25 करोड़ लोग मेरा परिवार- CM योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भावुक अंदाज में कहा, 'मेरा घर उत्तर प्रदेश है और राज्य के 25 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं. इनकी भलाई और तरक्की ही हमारा एकमात्र मिशन है.' ?उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि आज यूपी एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के मामले में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हाल ही में उद्घाटित हुआ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे विकास का श्रेय राज्य की जनता को देते हुए कहा कि यह सब जनता द्वारा विकासपरक सरकार चुनने के कारण ही संभव हो पाया है.

## पूरे देश में जंगलों को बचाने की जरूरत JSPCB की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, जानें क्यों कहा- हम कोई हेडमास्टर नहीं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में जंगलों को बचाने की जरूरत है. झारखंड जैसे कुछ राज्यों में प्राकृतिक इकोसिस्टम है, जिसे बचाकर रखना जरूरी है. ये बात सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कही. सीजेआई ने JSPCB (झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के वकील से कहा कि कुछ ही राज्य ऐसे हैं, जहां हम सच में अपने प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचा सकते हैं और झारखंड उनमें से एक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों में जंगल जैसी प्राकृतिक सुंदरता वाली जगहें हैं और उन्हें बचाने की जरूरत है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. हाई कोर्ट ने अप्रैल में जंगलों या वन भूमि की सीमाओं के पास पत्थरों के खनन या पत्थर तोड़ने वाली मशीनें लगाने की मंजूरी के सिलसिले में कई दिशा-निर्देश जारी किए थे.

### जनवरी में हाई कोर्ट ने दिया था ये निर्देश

इससे पहले जनवरी में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य में संरक्षित वनों की तय सीमाओं से एक किलोमीटर के दायरे में पत्थर के खनन या पत्थर तोड़ने वाली मशीनें लगाने के लिए कोई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने यह आदेश जेएसपीसीबी की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर पास किया था, जिसके तहत जंगल या वन भूमि के आसपास पत्थर के खनन और पत्थर तोड़ने वाली मशीनें लगाने के लिए निर्धारित न्यूनतम दूरी को 400-500 मीटर से घटाकर 250 मीटर कर दिया गया था. अप्रैल में पास आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि मंजूरी देने पर लगी रोक पत्थर के खनन मामले में जंगल या वन भूमि की सीमाओं से 500 मीटर के दायरे में, जबकि पत्थर तोड़ने वाली मशीनों के मामले में 400 मीटर के दायरे में लागू होगी. अब सुप्रीम कोर्ट ने जेएसपीसीबी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि बोर्ड ने अचानक दूरी कम कर दी थी.

### हम कोई हेडमास्टर नहीं हैं, जो हाई कोर्ट को सलाह दें

जेएसपीसीबी की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सब कुछ रुका हुआ है. इस पर पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट मामले पर विचार कर रहा है. वहां इसकी अंतिम सुनवाई होनी है. हाई कोर्ट को अंतिम आदेश देने दें. जब जेएसपीसीबी ने हाई कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र किया तो पीठ ने कहा कि हम अपने हाई कोर्ट्स का मनोबल नहीं गिरा सकते. हम कोई हेडमास्टर नहीं हैं, जो हाई कोर्ट को सलाह दें कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

## अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में एंट्री लेने पर वो कौन सा नारा लगा, जिस पर मुस्कुराते रहे राहुल गांधी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने 9 राज्यों के जिला चेयरमैन को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया था. इंदिरा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संबोधित किया. कार्यकम में जैसे ही राहुल गांधी ने एंट्री ली तो तो जोर-शोर से 'देश का पीएम कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो' के नारे लगने लगे. इस नारे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राहुल गांधी मुस्कुराते रहे. वहीं. अपने संबोधन में राहुल एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर दिखे. राहुल ने यहां करीब 45 मिनट का भाषण दिया. सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि आप नोट कर लीजिए नरेंद्र मोदी एक साल बाद पीएम नहीं रहेंगे. मैं ये जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कह रहा हूं. नोट करके रख लीजिए. मोदी मुझसे निगाह नहीं मिला पाते. हाल ही में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के एक कार्यक्रम में आपने वीडियो देखा होगा कि वो पहले मेरे पास आए तो आंख मिलाए बिना आगे बढ़ गए.

### जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए: राहुल गांधी

राहुल ने कहा, फिर उनको याद आया होगा कि राहुल तो कह चुका है कि मोदी उनसे आंख नहीं मिला पाते. तब वो दोबारा लौटकर मिलने आए. इसका कारण ये है कि मोदी कम्प्रोमाइज्ड पीएम हैं. बैठक में कांग्रेस सांसद ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, गरीबों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए. राहुल ने जेन-जी यानी छात्रों की बात करते हुए कहा कि जो छात्रों की गूंज कोटा में उठी उसे जन-जन तक ले जाइए. उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज के जिस तबके के साथ अन्याय हो उसको सिर्फ अल्पसंख्यक बोलने की बजाय सिख, मुस्लिम, पारसी या जैन जो हो उसको खुलकर बोलिए, डरिए मत.

### 'मुझसे शिकायत कीजिए, मैं एक्शन लूंगा'

उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का सिद्धांत है कि समाज के जिस भी तबके के साथ अन्याय हो, उसके साथ पार्टी खड़ी हो वरना कांग्रेस कांग्रेस नहीं रह जाएगी क्योंकि देश का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है. राहुल ने 9 राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्षों को ताकत देते हुए कहा कि आप लोग इसी लाइन पर काम कीजिए. अगर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष आपकी राह में रोड़ा अटकाए या सहयोग न करे तो मुझसे शिकायत कीजिए, मैं एक्शन लूंगा. इस अहम बैठक की जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने टीवी9 को बताया कि बैठक सफल रही. जल्द ही राहुल बाकी राज्यों के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्षो से मिलेंगे. साथ ही उन्होंने एक वाकिये का जिक्र करते हुए बताया कि जब सभी ने राहुल के साथ फोटो खिंचवाने की मांग की तो राहुल ने मंच पर बैठकर बाकियों को ऊपर बुलाने के बजाय कहा- आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं. फिर राहुल ने 12-14 जगह जाकर उनके साथ फोटो खिंचवाई.

# तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का NCPI में विलय

भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे घटनाक्रम दर्ज हैं जिन्होंने रातोंरात सत्ता के समीकरणों को बदलकर रख दिया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से 20 सांसदों का अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना एक ऐसा राजनीतिक भूचाल है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह घटना महज कुछ नेताओं का पाला बदलना नहीं है बल्कि एक सुस्थापित राजनीतिक दल के भीतर उपजे गहरे असंतोष और महत्वाकांक्षाओं के टकराव का परिणाम है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीब रहीं काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में हुआ यह विभाजन भारतीय लोकतंत्र की उस गतिशीलता को दर्शाता है जहां कोई भी संगठन पूरी तरह अजेय नहीं होता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय राजनीति में पाला बदलने और विचारधाराओं के साथ चलने की परंपरा रही है लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में सांसद एक साथ अपनी पुरानी वफादारी छोड़ते हैं तो इसके मायने बहुत गहरे होते हैं। यह घटना इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक असंतोष धीरे धीरे पककर एक बड़े विस्फोट का रूप ले लेता है।

इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की रूपरेखा बहुत ही रणनीतिक तरीके से तैयार की गई। 31 मई 2026 को काकोली घोष दस्तीदार को नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह दल कोई बहुत पुराना या स्थापित ताकत नहीं थी बल्कि इसे 2023 में ही पंजीकृत कराया गया था। अपनी स्थापना के बाद से यह संगठन राजनीतिक परिदृश्य के हाशिये पर ही था लेकिन 20 सांसदों के एकमुश्त विलय ने इसे अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। इसके बाद 14 जून 2026 को इस विलय और नए नेतृत्व की औपचारिक जानकारी भारत के निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई। निर्वाचन आयोग को समय पर सूचना देना इस बात का प्रमाण है कि बागी गुट कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि उन पर कोई वैधानिक संकट न आए।



इस विभाजन का सबसे दूरगामी प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति पर पड़ने वाला है। नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए इन 20 सांसदों ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। संसद के भीतर 20 सांसदों का एक झटके में सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में चले जाना विपक्ष की एकजुटता के लिए एक बड़ा आघात है। इससे न केवल संसद में संख्या बल का समीकरण पूरी तरह बदल गया है बल्कि विपक्षी दलों के उस मनोबल को भी गहरी ठेस पहुंची है जो वे आगामी चुनावों के लिए तैयार कर रहे थे। पश्चिम बंगाल जो हमेशा से गैर कांग्रेसी और गैर सत्ताधारी गठबंधनों का एक मजबूत गढ़ रहा है वहां से उठी यह बगावत अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दलों के लिए भी खतरे की घंटी है।

संविधान के जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब दसवीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून पर टिकी है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को मनमर्जी से दल बदलने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। लेकिन जब किसी संगठन के निर्वाचित सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग होता है और वह आवश्यक वैधानिक अनुपात को पूरा करता है तो सदस्यों की सदस्यता रद्द होने से बच जाती है। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग और संसदीय समितियां इस पूरे मामले का मूल्यांकन किस तरह करती हैं। यदि ये 20 सांसद अपनी सदस्यता बचाने में सफल रहते हैं तो यह काकोली घोष दस्तीदार की एक बहुत बड़ी वैधानिक और रणनीतिक जीत मानी जाएगी।

दल बदल कानून का मूल उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था लेकिन समय समय पर नेताओं ने इसके भीतर मौजूद कानूनी रास्तों का उपयोग अपने हित में किया है। अब जब मामला निर्वाचन आयोग के विचाराधीन है तो सभी कानूनी पहलुओं की बहुत ही बारीकी से जांच की जाएगी। इस निर्णय का प्रभाव केवल इन सांसदों के भविष्य पर ही नहीं बल्कि भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था और भविष्य में होने वाले ऐसे हर विभाजन पर नजीर के रूप में काम करेगा।

तृणमूल कांग्रेस के लिए यह स्थिति गहन आत्मनिरीक्षण की है। दशकों के लंबे और कड़े संघर्ष के बाद जिस दल ने पश्चिम बंगाल में अपना अभेद्य किला बनाया था उस किले में इतनी बड़ी सेंध लगना नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। दल को अब न केवल अपने बचे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतना होगा बल्कि जमीन पर जनता के बीच भी यह संदेश देना होगा कि यह टूट उनके जनाधार को कमजोर नहीं कर सकती। राज्य का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि यहां की जनता ने हमेशा सशक्त और स्पष्ट विचारधारा वाले नेतृत्व को पसंद किया है। वामपंथी दलों के लंबे शासनकाल को समाप्त करके जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थीं तब जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया था। अब यही बदलाव की मांग अगर उनके अपने ही संगठन के भीतर से उठ रही है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

दूसरी ओर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन सभी 20 सांसदों को एकजुट रखना और राज्य में अपने लिए एक नया और मजबूत मतदाता आधार तैयार करना होगा। पश्चिम बंगाल की जनता जो राजनीतिक रूप से अत्यधिक जागरूक मानी जाती है वह इस पाला बदल को वैचारिक क्रांति मानती है या अवसरवादिता यह आने वाले चुनाव परिणामों में ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा। इसके अतिरिक्त यह घटना क्षेत्रीय दलों की उस कमजोरी को भी उजागर करती है जहां संगठन का पूरा ढांचा किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। जब दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे बढ़ने और अपनी बात रखने का उचित मंच नहीं मिलता तो इस तरह के विद्रोह जन्म लेते हैं। काकोली घोष दस्तीदार का कदम अन्य राज्यों में ऐसे नेताओं को भी प्रेरित कर सकता है जो अपने संगठनों में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर होता है जब वे क्षेत्रीय दलों के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़कर अपने राजनीतिक आधार का विस्तार करते हैं। नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल करने के पीछे भी यही रणनीति काम कर रही है। इससे सत्ताधारी गठबंधन को उस क्षेत्र में भी अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका मिलेगा जहां वह अब तक कमजोर माना जाता रहा है।

**अंततः** यह घटनाक्रम केवल राज्य तक सीमित रहने वाला नहीं है। यह पूरे देश के राजनीतिक विचारकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता के केंद्रीकरण और आंतरिक लोकतंत्र की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। 2026 का यह वर्ष भारतीय राजनीति में नए गठबंधनों पुराने रिश्तों के टूटने और महत्वाकांक्षाओं की नई उड़ान के लिए याद किया जाएगा। काकोली घोष दस्तीदार के रूप में उभरा नया नेतृत्व और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिला उनका समर्थन भविष्य की राजनीति की एक ऐसी पटकथा लिख रहा है जिसका हर पन्ना अनिश्चितताओं से भरा है।

महेन्द्र तिवारी

# मोदी सरकार में वो समस्याएं जो अभी तक नहीं सुधरीं

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2014 के बाद से अब तक भारत ने काफी तरक्की की है लेकिन इसमें यह भी है कि अभी तक बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें सुधार होना बाकी है। 2014 से 2026 तक 12 साल की सत्ता में मोदी सरकार ने योजनाओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक छवि पर काम किया। लेकिन कुछ संरचनात्मक समस्याएं ऐसी हैं जो चुनावी नारों और सरकारी रिपोर्टों के बावजूद ज़मीन पर बनी हुई हैं। ये समस्याएं आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे जुड़ती हैं। इसमें सबसे पहले आती है बेरोज़गारी और अनौपचारिक क्षेत्र की अस्थिरता। हालांकि बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन अभी कई प्रयास करने बाकी हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बेरोज़गारी दर 2017 के मुकाबले घटी है। लेकिन हकीकत में समस्या की प्रकृति बदली है। गुणवत्तापूर्ण रोज़गार की कमी भारतीयों को खल रही है। हर साल 1.2 करोड़ युवा श्रम बाजार में आते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वेतन बढ़ोतरी धीमी है। आईटी और स्टार्टअप में छंटनी ने मिडिल क्लास की चिंता बढ़ाई है। अनौपचारिक क्षेत्र पर असरः नोटबंदी, GST और कोविड के बाद छोटे दुकानदार, ठेले वाले और दिहाड़ी मजदूर पूरी तरह उभर नहीं पाए। CMIE और NSSO के सर्वे बताते हैं कि स्वरोज़गार बढ़ा है, लेकिन ये ज़्यादातर मजबूरी का स्वरोज़गार है। कृषि संकट और किसान की आय के लिए बहुत समय से बात चल रही है लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस नीति नहीं बन सकी है। 2016 में सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। 2026 तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। MSP की सीमित पहुंच : सिर्फ गेहूं-धान के किसान ही MSP का फायदा ले पाते हैं। दाल, तिलहन, फल-सब्जी वाले किसान मंडी के भाव पर निर्भर हैं। कर्ज और जलवायु जोखिमः को लेकर किसान हमेशा से परेशान रहा है। फसल बीमा योजना ने कुछ राहत दी, लेकिन अतिवृष्टि, सूखा और आवारा पशु की समस्या बनी हुई है। तीन कृषि कानूनों के विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और बड़े कृषि सुधार रुके हुए हैं।

**शिक्षा और स्वास्थ्य में गुणवत्ता का अंतर**

शिक्षाः NEP 2020 ने ढांचा बदला, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, ड्रॉपआउट रेट और लर्निंग आउटकम अब भी कमजोर हैं। स्वत्र रिपोर्ट लगातार बताती है कि कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाता। इसी तरह स्वास्थ्यः आयुष्मान भारत ने कवरेज बढ़ाया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर, नर्स और दवाओं की कमी है। निजी अस्पताल महंगे हैं, और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च भारत में अब भी GDP का 50% से ज्यादा है।



महंगाई का मध्यम वर्ग पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। तेल, सब्जी, दाल और किराये की कीमतों में उछाल ने मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सरकार ने टैक्स स्लैब बदले, लेकिन प्रत्यक्ष कर का बोझ अब भी वेतनभोगी वर्ग पर ज्यादा है। कोर महंगाई भले नियंत्रण में रही हो, लेकिन खाद्य महंगाई 2022-2024 में दो बार 10% पार कर गई। RBI के बार-बार रेपो रेट बढ़ाने से EMI बढ़ी और घर खरीदना मुश्किल हुआ। नौकरशाही और भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रहीं हैं। DBT और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बिचौलियों को कम किया, लेकिन ज़मीन-रजिस्ट्री, पुलिस, म्यूनिसिपल सर्विस में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। विपक्ष का आरोप है कि ED, CBI जैसी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ा है। वहीं सरकार कहती है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। नतीजा ये है कि आम आदमी का भरोसा सिस्टम पर आंशिक ही बहाल हुआ है।

सामाजिक ध्रुवीकरण और संवाद की कमी पिछले 12 साल में धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय बहस में हावी रहे। इससे विकास और रोज़गार जैसे मुद्दे कई बार बैकसीट पर चले गए। मीडिया और सिविल सोसाइटी का स्पेस सिकुड़ने की शिकायत विपक्ष और पत्रकार संगठनों से आती रही है। सरकार का पक्ष है कि फेक न्यूज़ और अस्थिरता रोकने के लिए नियम जरूरी हैं। राज्य-केंद्र संबंध और संघीय ढांचा GST लागू होने के बाद राज्यों को मुआवज़ा देने का वादा 2022 में खत्म हो गया। अब कई राज्य कहते हैं कि उनका फिस्कल स्पेस सिकुड़ गया है।

केंद्रीय योजनाओं के नाम पर राज्यों की भूमिका सीमित हो गई है, जिससे संघीय संतुलन पर सवाल उठते हैं। सुधार हुआ, पर असमान गति से मोदी सरकार ने बुनियादी सुविधाओं, डिजिटल ट्रांजैक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ठोस काम किया है। उज्ज्वला, जनधन, सड़क, रेल और UPI इसका उदाहरण हैं। लेकिन रोज़गार की गुणवत्ता, कृषि आय, शिक्षा-स्वास्थ्य की ग्राउंड लेवल क्वालिटी, और महंगाई जैसी समस्याएं अभी भी सिस्टम की कमज़ोरी दिखाती हैं। 2026 तक सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी तेज़ करे, ताकि ये समस्याएं चुनावी मुद्दे बनकर न रह जाएं बल्कि हल हों।

# भागवत बोले- इतिहासकार केवल नैरेटिव बनाते हैं

**हल्दीघाटी के युद्ध में विजय केवल महाराणा प्रताप की हुई, मुगलों को पीछे हटना पड़ा**

उदयपुर में आयोजित राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने हल्दीघाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप के अद्वितीय व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इतिहासकारों ने इस युद्ध को लेकर केवल एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, जबकि वास्तविकता यह है कि हल्दीघाटी के युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की ही हुई थी। उन्होंने कहा कि मुगल इतिहासकारों के विवरणों में भी यह उल्लेख मिलता है कि युद्ध के दौरान मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा था। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि मुगल सेना पीछे खिसकी, भयभीत हुई और युद्ध के बाद सुरक्षित स्थानों में सीमित रहने को विवश हो गई, तो विजय किसकी मानी जानी चाहिए। भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह विजय केवल महाराणा प्रताप की ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और स्वतंत्रता के संकल्प की विजय थी।

महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन महानतम योद्धाओं में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। वे केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, बल्कि राष्ट्र गौरव, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के जीवंत प्रतीक थे। जिस समय भारत के अनेक शासक मुगल सत्ता के सामने झुक चुके थे, उस समय महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान को सर्वोच्च मानते हुए संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मेवाड़ की धरती पर विदेशी सत्ता का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि हल्दीघाटी का युद्ध केवल महाराणा प्रताप और उनकी सेना का युद्ध नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज का संघर्ष था। मेवाड़ की जनता, भील समुदाय और विभिन्न वर्गों ने इस युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। यही कारण था कि संसाधनों की कमी के बावजूद प्रताप का संघर्ष वर्षों तक चलता रहा। उन्होंने कहा कि अकबर के पास विशाल सेना, अपार धन और असीमित संसाधन थे, जबकि महाराणा प्रताप सीमित साधनों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता के संकल्प को जीवित रखा।

हल्दीघाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। 18 जून 1576 को लड़े गए इस युद्ध में एक ओर मुगल साम्राज्य की विशाल शक्ति थी और दूसरी ओर मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित महाराणा प्रताप का अदम्य साहस। युद्ध के दौरान प्रताप ने जो पराक्रम दिखाया, उसने उन्हें अमर बना दिया। उनका प्रिय अश्व चेतक भी वीरता और स्वामिभक्ति का अद्भुत उदाहरण बन गया। चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया, जिसके कारण उसका नाम भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। डॉ. मोहन भागवत ने युद्ध के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुगल सेना को कई अवसरों पर पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध के प्रथम चरण में मुगल पीछे खिसके, यदि दूसरे चरण में महाराणा प्रताप ने दुश्मन के प्रमुख योद्धाओं को चुनौती दी और यदि युद्ध के बाद मुगल सेना भय के कारण सुरक्षित स्थानों में सीमित रहने को विवश हुई, तो यह स्पष्ट संकेत है कि युद्ध का नैतिक और वास्तविक पलड़ा महाराणा प्रताप के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि इतिहास को तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि केवल स्थापित धारणाओं के आधार पर।



महाराणा प्रताप का जीवन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। वे आदर्श शासन, जनकल्याण और नैतिक मूल्यों के भी प्रतीक थे। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत सुख और वैभव को महत्व नहीं दिया। कठिन परिस्थितियों में जंगलों और पहाड़ों में जीवन व्यतीत करना पड़ा, परिवार को कष्ट सहने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि उन्हें 'हिंदुआ सूरज' कहा जाता है। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान के प्रहरी थे। भागवत ने कहा कि महाराणा प्रताप कभी स्वार्थ के लिए नहीं लड़े। उनका संघर्ष समाज, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए था। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के हित को सर्वोच्च स्थान दे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, यदि संकल्प अडिग हो तो विजय का मार्ग अवश्य निकलता है।

उदयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए संत-महात्माओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भी महाराणा प्रताप के योगदान को स्मरण किया। निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर ने कहा कि यह भूमि बलिदान और त्याग की भूमि है तथा समाज को एकजुट रहकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार चुनौतियों के बीच भी राष्ट्र की महानता और संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है।

महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक स्मरण समारोह नहीं था, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत करने का प्रयास भी था। इस अवसर पर वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और स्वाभिमान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। आज भी महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही साहस, त्याग और देशभक्ति की भावना जागृत हो उठती है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे नायक हैं जिनकी महानता समय के साथ और अधिक बढ़ती गई है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि शक्ति केवल सेना और धन में नहीं होती, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और मातृभूमि के प्रति समर्पण में भी होती है।

डॉ. मोहन भागवत के वक्तव्य ने एक बार फिर हल्दीघाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप के संघर्ष को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। चाहे इतिहास की व्याख्याएं अलग-अलग हों, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि महाराणा प्रताप भारतीय स्वाभिमान के सबसे उज्ज्वल प्रतीकों में से एक हैं। उन्होंने पराधीनता के स्थान पर संघर्ष को चुना, समझौते के स्थान पर सम्मान को चुना और व्यक्तिगत हितों के स्थान पर राष्ट्रहित को चुना। यही कारण है कि वे आज भी करोड़ों भारतीयों के हृदय में आदर्श, प्रेरणा और गौरव के रूप में विराजमान हैं। महाराणा प्रताप का जीवन भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की ऐसी अमर गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।

कांतिलाल मांडोत

# कविता

## अपनी सादगी में मुस्कुरा देना।




अपनी सादगी में मुस्कुरा देना।

मिल जाओ कहीं तो मुस्कुरा देना,
दिल की हर कशिश में मुस्कुरा देना।

विषम स्थिति में बड़ी दवा मुस्कुरा देना,
ग़म की हर घड़ी में मुस्कुरा देना।

जब भी ज़िंदगी इम्तिहाँ लेने लगे,
हौसलों की लौ में मुस्कुरा देना।

दर्द जब हद से गुज़रने लगे कभी,
अश्क़ की नमी में मुस्कुरा देना।

राह में जब अँधेरों का राज हो,
दिल की रोशनी में
मुस्कुरा देना।

लोग जब तुम्हें समझ न पाएँ कभी,
अपनी सादगी में मुस्कुरा देना।

वक़्त जब ख़िलाफ़तों में ढलने लगे,
सब्र के सागर में मुस्कुरा देना।

टूटते हुए ख़्वाब जब सताएँ बहुत,
नई एक सदी में मुस्कुरा देना।

इश्क़ हो, वफ़ा हो या जुदाई का सफ़र,
हर एक बंदगी में मुस्कुरा देना।

'संजीव' ये हुनर गर आ गया तुम्हें,
ज़िंदगी की हर घड़ी में मुस्कुरा देना।

संजीव ठाकुर

# दैनिक राशिफल

**मेष** कल का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
शुभ रंगः लाल 7 शुभ अंकः 9

**वृषभ** धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंगः सफेद 7 शुभ अंकः 6

**मिथुन** व्यापार में लाभ के संकेत हैं। संचार कौशल के कारण आपके कार्य बनेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी।
शुभ रंगः हरा 7 शुभ अंकः 5

**कर्क** भावनाओं पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।
शुभ रंगः चांदी 7 शुभ अंकः 2

**सिंह** मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
शुभ रंगः सुनहरा 7 शुभ अंकः 1

**कन्या** कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंगः हरा 7 शुभ अंकः 5

**तुला** सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
शुभ रंगः गुलाबी 7 शुभ अंकः 6

**वृश्चिक** महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें। करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
शुभ रंगः लाल 7 शुभ अंकः 9

**धनु** भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।
शुभ रंगः पीला 7 शुभ अंकः 3

**मकर** धन निवेश में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।
शुभ रंगः नीला 7 शुभ अंकः 8

**कुंभ** साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
शुभ रंगः आसमानी 7 शुभ अंकः 4

**मीन** स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं।
शुभ रंगः पीला 7 शुभ अंकः 7

# पत्तियाँ काटने से नहीं, जड़ों को काटकर ही मिटेगा परीक्षा माफिया

**[री-एग्जाम, री-लीक, री-बैनः विश्वासघात का अंतहीन चक्रव्यूह]**

**[डिजिटल स्वतंत्रता की बलि चढ़ाकर क्या हम परीक्षा की पवित्रता बचा पाएंगे?]**

भारत की परीक्षा-व्यवस्था एक बार फिर उस मोड़ पर है जहाँ प्रश्न केवल नकल या लीक का नहीं, बल्कि भरोसे की बुनियाद के दरकने का है। नीट-यूजी री-एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध ने इस बहस को और तीखा बना दिया है। यह कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की सिफारिश पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत उठाया गया है। इसके तहत 22 जून तक टेलीग्राम की एक्सेस बंद रहेगी और मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून तक निष्क्रिय रहेगा। एक ओर इसे परीक्षा सुरक्षा की तात्कालिक ढाल माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे डिजिटल स्वतंत्रता पर असंतुलित हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह अस्थायी बैन परीक्षा सुधार की दिशा में एक ठोस जीत है या फिर जड़ों को छोड़कर पत्तियों को काटने की पुरानी आदत?

नीट-यूजी परीक्षा लीक का दर्द नया नहीं है। मई 2026 में नीट-यूजी परीक्षा (3 मई को आयोजित) रद्द करनी पड़ी क्योंकि राजस्थान (विशेषकर सीकर-जयपुर क्षेत्र) में गेस पेपर सर्कुलेशन और कथित पेपर लिक के आरोपों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए थे। इससे लगभग 22-23 लाख छात्र प्रभावित हुए। कुछ छात्रों की आत्महत्याओं ने इस त्रासदी को प्रशासनिक विफलता से आगे बढ़ाकर मानवीय संकट में बदल दिया। सरकार और एनटीए का तर्क इस कदम को आपातकालीन सुरक्षा कवच के रूप में प्रस्तुत करता है। उनका कहना है कि टेलीग्राम पर सक्रिय चैनल न केवल फर्जी पेपर बेच रहे थे, बल्कि संदेशों को एडिट कर बाद में उन्हें 'प्रमाण' की तरह पेश कर रहे थे।

यही तकनीकी लचीलापन धोखाधड़ी का नया हथियार बन गया। री-एग्जाम की अत्यंत संवेदनशील अवधि में ऐसे नेटवर्क को प्रभावी रूप से रोकने के लिए अस्थायी प्रतिबंध को आवश्यक एवं तात्कालिक कदम माना गया। यह किसी स्थायी सेंसरशिप की शुरुआत नहीं, बल्कि सीमित समय के लिए डिजिटल दरारों को बंद करने की कोशिश है। पर सवाल यह है कि क्या व्यवस्था की यह 'तात्कालिक मरम्मत' दीर्घकालिक सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, या यह केवल एक अस्थायी पट्टी है जो गहरे घाव को छुपा देती है?

फिर भी, इस कदम की आलोचना जायज है। टेलीग्राम पर करोड़ों भारतीय निर्भर हैं - छात्र सामग्री शेयर करते हैं, छोटे व्यापारी काम चलाते हैं, पत्रकार सूचना इकट्ठा करते हैं। एक पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना वीपीएन के दौर में कितना प्रभावी होगा, यह बहस का विषय है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसी संस्थाएं इसे अतिरंजित और असंवैधानिक बता रही हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, लेकिन जब वह लाखों ईमानदार छात्रों के हक में बाधक बन जाए तो क्या सरकार को हाथ पर हाथ रखकर बैठना चाहिए? संतुलन जरूरी है। बैन अस्थायी है, लक्षित है, लेकिन लंबे समय में यह समाधान नहीं।

पर समस्या केवल डिजिटल मंचों की नहीं, बल्कि उस पूरी संरचना की है जो लीक को जन्म देती है। परीक्षा प्रणाली की कमजोर कड़ियाँ–प्रिंटिंग प्रेस की सुरक्षा, परिवहन की निगरानी, केंद्रों की जवाबदेही और भ्रष्टाचार की छायाएँ–सब मिलकर इस संकट की जमीन तैयार करती हैं। टेलीग्राम या कोई अन्य प्लेटफॉर्म केवल माध्यम है, अपराध का मूल स्रोत नहीं। यदि संरचना ही छिद्रपूर्ण रहेगी, तो अपराधी हर नए माध्यम को अपने हित में ढाल लेंगे। इसलिए केवल डिजिटल नियंत्रण से समाधान की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे दीवारों पर रंग कर भवन की नींव को मजबूत मान लेना।

अब समय आ गया है कि परीक्षा व्यवस्था को तकनीकी और संरचनात्मक दोनों स्तरों पर पुनर्परिभाषित किया जाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग (सीबीटी) का व्यापक उपयोग केवल आधुनिकता नहीं, बल्कि सुरक्षा की आवश्यकता है। एआई आधारित प्रॉक्टरिंग,




बायोमेट्रिक सत्यापन और एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र वितरण प्रणाली लीक की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ब्लॉकचेन जैसी तकनीक प्रश्नपत्र की ट्रेसबिलिटी और पारदर्शिता को नई मजबूती दे सकती है। यदि तकनीक को केवल सहायक नहीं, बल्कि प्रणाली का केंद्र बनाया जाए, तो भरोसे की नींव पुनः स्थापित की जा सकती है।

झडिजिटल प्लेटफॉर्म रेगुलेशन का प्रश्न अब टालने योग्य नहीं है। धारा 69 आवश्यक है, पर इसका उपयोग संतुलित और पारदर्शी होना चाहिए। टेलीग्राम समाधान नहीं, यह केवल आपातकालीन कदम है जो तत्काल धोखाधड़ी रोक सकता है। सरकार को टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर प्रभावी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए, ताकि संदिग्ध चैनल तुरंत ब्लॉक हो सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी आधारित निगरानी तंत्र विकसित होना चाहिए, जहाँ संदिग्ध गतिविधियों की तेज पहचान और निष्कासन हो सके। नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी है। एनटीए का दावा है कि इससे फ्रॉड पर अंकुश लगेगा, लेकिन असली सफलता तभी होगी जब छात्रों को बार-बार री-एग्जाम न देना पड़े और उनकी मेहनत सुरक्षित रहे, वरना लगातार विवाद उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करते रहेंगे।

परीक्षाओं की पवित्रता राष्ट्र के भविष्य से जुड़ी है। टेलीग्राम पर यह अस्थायी प्रतिबंध न तो विजय का शंखनाद है और न ही लोकतांत्रिक अधिकारों पर स्थायी चोट। यह एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है–एक ऐसे तंत्र की जो बार-बार दरकता है और हर बार अस्थायी सहारे से खड़ा किया जाता है। असली प्रश्न यह है कि क्या हम हर संकट पर प्लेटफॉर्म बदलते रहेंगे या उस व्यवस्था को ही बदलेंगे जो संकट को जन्म देती है। परीक्षा की शुचिता कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास की रीढ़ है। यदि यह रीढ़ टूटती रही, तो न केवल परीक्षाएँ, बल्कि पूरा शिक्षा-तंत्र अविश्वास की धूल में बदल जाएगा। अब समय है कि हम सतह पर नहीं, जड़ों पर वार करें–और एक ऐसी व्यवस्था गढ़ें जहाँ 'लीक' असंभव नहीं तो कम से कम असहज अवश्य हो। तभी छात्रों का विश्वास लौटेगा और सपनों का हत्यारा माफिया बेकार हो जाएगा।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

**स्वामी-** स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

## संक्षिप्त खबरें

### अयोध्या में सीबीआई टीम का छापा, वित्त एवं लेखा विभाग अमेठी में करोड़ों के घोटाले में पड़ताल

अमेठी में वित्त एवं लेखा विभाग में करोड़ों के घोटाले को लेकर अयोध्या के साथ लखनऊ, प्रतापगढ़ और कुशीनगर में एक साथ छापेमारी की

**लखनऊ।** अमेठी में वित्त एवं लेखा विभाग में करोड़ों के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने बुधवार को सुबह अयोध्या सहित अन्य नगरों में छापा मारा। राम नगरी में सीबीआई की टीम के इस छापे पर खलबली मच गई और लोगों ने सोचा की राम मंदिर में चढ़ावा को लेकर टीम पड़ताल कर रही है। सीबीआई की टीम ने कोर्ट के आदेश पर अमेठी में वित्त एवं लेखा विभाग में करोड़ों के घोटाले को लेकर अयोध्या के साथ लखनऊ, प्रतापगढ़ और कुशीनगर में एक साथ छापेमारी की। अयोध्या में टीम सुबह सात बजे पहुंची और कोतवाली नगर के देवकाली पुलिस चौकी के निकट पवन कुमार मालवीय के घर पड़ताल की। टीम ने आठ बजे तक पड़ताल समाप्त कर दी। सीबीआई की डीआईजी शिवानी तिवारी के निर्देशन में टीम ने अयोध्या में छापेमारी की। अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग के सात करोड़ से अधिक के घोटाले में बुधवार को सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच संभालने के बाद सीबीआई ने अयोध्या सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है। सात करोड़ से अधिक के घोटाले में सीबीआई ने आठ टीमें गठित कर जांच शुरु की और लखनऊ व अयोध्या समेत आठ जिलों में दस्तावेज खंगाले। टीम घोटाले के साक्ष्य जुटाने में जुटी है। सीबीआई ने लखनऊ, प्रतापगढ़, अयोध्या, अमेठी और कुशीनगर में छापेमारी से वित्त एवं लेखा अनुभाग में करोड़ों के घोटाले पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संदिग्धों और मामले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर जांच चल रही है। सीबीआई की टीमें अमेठी में शिक्षा विभाग के घोटाले में दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाल रही हैं।

### ओमप्रकाश राजभर के दावे पर अखिलेश का पलटवार, बोले- यूपी में पाला बदलने को तैयार बैठे हैं भाजपा के ही विधायक

अखिलेश यादव ने कहा कि लालच देकर और डराकर विधायक व एमएलसी तोड़े

**लखनऊ।** समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुभासपा अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने ओमप्रकाश राजभर के सपा सांसदों के टूट वाले दावे पर जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर बुधवार को पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओमप्रकाश राजभर के बयान के सवाल पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाना और दाना, कब तक चलेगा ये अफसाना। इसके बाद में कहा कि भाजपा इसी तरह से काम करती है, उन्होंने यूपी में पहले सपा के विधायक व एमएलसी तोड़े थे। अखिलेश यादव ने कहा कि लालच देकर और डराकर विधायक व एमएलसी तोड़े। उन्होंने कहा कि जो डरेगा वो तो जाएगा, बहादुर लोग होने चाहिए। यूपी में तो भाजपा के ही विधायक पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। कुछ लोग समय पर पत्ते खोलते हैं। सपा पूरी तरह मजबूत है और पार्टी कई बार उतार-चढ़ाव देख चुकी है।

**भाजपा के लिए धर्म का मतलब धन**

सपा प्रमुख ने राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण को लेकर कहा कि भाजपा के लिए धर्म का मतलब धन है। वहां के सीसी कैमरों की फुटेज गायब है, क्योंकि उससे चढ़ावा चोरी के राज खुल जाएगा। उन्होंने गोरखपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली के आंकड़े पेश किए और गोरखपुर में जल्द कार्यकर्ता सम्मेलन करने की बात कही। समय से पहले विधानसभा चुनाव के प्रश्न पर कहा कि सारा मामला खाद का है। अगर सरकार खाद का इंतजाम नहीं कर पाई तो चुनाव नवंबर में ही हो जाएंगे। उन्होंने इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर के पूरा होने पर राम मंदिर में दर्शन करने की बात भी दोहराई।

# लखनऊ मेट्रो में अब एक कार्ड से पूरे देश में सफर

● लखनऊ मेट्रो जल्द ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लॉन्च करेगी, जिससे यात्री देश भर की मेट्रो में एक ही कार्ड से सफर कर सकेंगे

● मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड तीन महीने में बंद हो जाएंगे और उनका बैलेंस एनसीएमसी में ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए यात्रियों को इसे जल्द खत्म करना होगा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** अब कोच्चि सहित दूसरे शहरों की मेट्रो में सफर के लिए वहां टिकट की लाइन लगने की जरूरत नहीं होगी। लखनऊ सहित देश भर की इन मेट्रो में सफर एक ही कार्ड पर हो सकेगा। कानपुर और आगरा के बाद लखनऊ में भी नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने एनसीएमसी की सुविधा शुरू करने के लिए ट्रायल पूरा कर लिया है। एक सप्ताह के भीतर यह सुविधा लांच हो जाएगी। हालांकि एनसीएमसी कार्ड लांच होने के तीन माह के बाद मौजूदा गो स्मार्ट कार्ड को बंद किया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को एनएसीएमसी लांच होने के तीन माह के भीतर गो स्मार्ट कार्ड के बैलेंस को समाप्त करना होगा। इस कार्ड का बैलेंस एनसीएमसी में ट्रांसफर नहीं होगा। यात्रा के किराए में 10 प्रतिशत छूट देने की मौजूदा कार्ड की व्यवस्था एनसीएमसी में भी जारी रहेगी। लखनऊ मेट्रो ने लगभग डेढ़ लाख गो स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। प्रतिदिन लगभग 90 हजार यात्री मेट्रो में सफर करते हैं। इसमें 45 हजार यात्री नकद राशि देकर टोकन, क्यूआर कोड से सफर करते हैं। वहीं, डेढ़ लाख स्मार्ट कार्ड के बाद भी केवल 45 हजार लोग गो स्मार्ट कार्ड से सफर करते हैं। लखनऊ मेट्रो ने जिस एयरटेल पेमेंट बैंक से एनसीएमसी जारी करने का करार किया है, वह पुराने कार्ड के बदले नए कार्ड जारी करने पर जमा होने वाली 100 रुपये की सुरक्षा राशि नहीं लेगी। मौजूदा कार्ड की सुरक्षा राशि के बदले ही नया कार्ड जारी हो जाएगा। इसके लिए कानपुर व आगरा की तरह केवाइसी की जरूरत नहीं होगी। यात्री को अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराना होगा उसपर ही एक ओटीपी आने के साथ एनसीएमसी जारी हो जाएगा।यह कार्ड देश के कई बैंक भी जारी करते हैं। ऐसे में यात्री अपने बैंक से ही नए कार्ड जारी करवा सकते हैं। एनसीएमसी से यात्री ट्रेन में सीधे प्रवेश कर सकेंगे और यात्रा का किराया कार्ड से स्वतः कट जाएगा। इससे यात्री शापिंग करने के साथ एटीएम से नकदी भी निकाल सकेंगे। इससे पार्किंग का भुगतान भी किया जा सकेगा। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने एनसीएमसी का आटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम तैयार किया है।

**लगातार हो रहा बदलाव**

लखनऊ मेट्रो का आटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम बहुत पुराना है। इस कारण अब तक केवल टोकन प्रणाली और गो स्मार्ट कार्ड से सफर हो पा रहा था। फरवरी माह में ही मेट्रो प्रशासन ने क्यूआर कोड वाले टिकट की प्रणाली लागू की थी। इसके लिए एक अलग आटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट लगाया गया। इसी के तहत एनसीएमसी का ट्रायल भी मेट्रो प्रशासन ने शुरू कर दिया था।

# किसान दिवस में जैविक खेती पर जोर, अधिकारियों ने बताए लाभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लालगंज (रायबरेली)।** तहसील सभागार में बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक खेती के महत्व और इसके लाभों की जानकारी दी। गोष्ठी की अध्यक्षता जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने की। उन्होंने कहा कि बदलते समय में जैविक खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। इससे फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है और किसानों को बाजार में बेहतर मूल्य मिल सकता है। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे आय बढ़ाने के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के कम इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता भी लंबे समय तक बनी रहती है। जैविक तरीके से तैयार खाद्यान्न स्वास्थ्य के लिए भी अधिक लाभकारी होते हैं। गोष्ठी में किसानों ने खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए शासन द्वारा संचालित किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर भूमि संरक्षण अधिकारी जगदीश यादव, कृषि वैज्ञानिक अभिलाष सिंह मौर्य, नाबार्ड अधिकारी रविशंकर, तहसीलदार शिवम राठौड़, कंप्यूटर सहायक आदित्य कुमार शुक्ला, बीज भंडार प्रभारी मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

# पीटीआर बाध्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दम्पति शिक्षक संघ का प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा

● मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ में दम्पति शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने गतिमान अंतरजनपदीय स्थानांतरण (पीटीआर) नीति में व्यापक संशोधन की एक सूत्रीय मांग को लेकर बुधवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि वर्तमान स्थानांतरण नीति का उद्देश्य विशेष परिस्थितियों से प्रभावित शिक्षकों को राहत प्रदान करना, पारिवारिक एकता को मजबूत करना तथा मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराना है, लेकिन नीति के कुछ प्रावधान स्थानांतरण में बाधक बन रहे हैं और शिक्षकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ के अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी सेवा में कार्यरत दम्पति शिक्षकों को पीटीआर (PTR) की बाध्यता से मुक्त रखते हुए उन्हें स्थानांतरण का अवसर दिया जाए तथा वर्तमान पीटीआर को स्थानांतरण का एकमात्र आधार न बनाया जाए। उन्होंने मांग की कि स्थानांतरण का लाभ केवल बेसिक शिक्षा परिषद के दम्पति शिक्षकों तक सीमित न रहकर अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत जीवनसाथियों को भी दिया जाए। संघ की उपाध्यक्ष साधना ने कहा कि जो दम्पति शिक्षक अपने गृह जनपद से दूर अथवा अलग-अलग जनपदों में कार्यरत हैं, उन्हें एक ही जनपद में स्थानांतरण का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे परिवार के साथ रहकर सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पूर्व भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। प्रशासन ने मांगों को जायज तो माना है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही मांगें पूरी नहीं की गईं तो दम्पति शिक्षक संघ अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने को बाध्य होगा।

# जुआ खेलते चार युवक गिरफ्तार, नकदी व ताश के पत्ते बरामद

**लालगंज (रायबरेली)।** कोतवाली पुलिस ने आम की बाग में जुआ खेल रहे चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने आलमपुर गांव स्थित एक आम की बाग में छापेमारी की। मौके पर कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेलते मिले। पुलिस ने त्रिवेदीपुर नई बस्ती निवासी संजय, नवरंग सिंह का पुरवा निवासी दीपक, सुरेंद्र और संदीप उर्फ नादे को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 1620 रुपये नकद, 52 ताश के पत्ते, एक गमछा और तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों के विरुद्ध जुआ निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आवश्यक कार्रवाई के बाद मोबाइल फोन वापस कर आरोपियों को नोटिस देकर रिहा कर दिया गया।

# अरुण सॉयल लैब प्राइवेट लिमिटेड में तकनीकी सर्वेक्षण सम्पन्न

**लखनऊ।** राजधानी लखनऊ में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ के तत्वावधान में अरुण सॉयल लैब प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ में एक विशेष तकनीकी सर्वेक्षण (Technical Survey) का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभियंताओं एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने प्रयोगशाला में उपलब्ध अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों तथा विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को नवीनतम परीक्षण तकनीकों, भू-तकनीकी जांच प्रक्रियाओं तथा औद्योगिक कार्यप्रणालियों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में श्री अरुण सिंह, प्रबंध निदेशक, अरुण सॉयल लैब प्राइवेट लिमिटेड ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा संस्थान की गतिविधियों एवं आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं पेशेवर संस्थाओं के मध्य तकनीकी सहयोग तथा ज्ञान का आदान-प्रदान तकनीकी प्रगति एवं गुणवत्ता सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम का आयोजन इं. निरंजन सिंह, चेयरमैन, अरुण सॉयल लैब प्राइवेट लिमिटेड के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में सम्पन्न हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे तकनीकी सर्वेक्षण अभियंताओं को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ उद्योग एवं पेशेवर संस्थाओं के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर इं. अनुराग कपूर ने 'ओवरव्यू ऑफ जिओटेक्नीकल इन्वेस्टीगेशन एंड इटस इंटरप्रिटेशन' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि किसी भी भवन, पुल, सड़क अथवा अन्य अवसंरचनात्मक परियोजना की सफलता के लिए भूमि की प्रकृति एवं उसकी इंजीनियरिंग विशेषताओं का सही आकलन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भू-तकनीकी जांच की विभिन्न विधियों, मृदा परीक्षणों, फील्ड इन्वेस्टिगेशन तकनीकों तथा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भू-तकनीकी जांच के निष्कर्षों का सही मूल्यांकन सुरक्षित, टिकाऊ एवं किफायती निर्माण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर संस्थापक सदस्य सुधाकर सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ से आए सभी अभियंताओं एवं अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे तकनीकी सर्वेक्षण उद्योग एवं पेशेवर संस्थाओं के मध्य ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं तथा अभियंताओं को नवीनतम तकनीकी प्रगति एवं व्यावहारिक अनुभवों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इं. वी.पी. सिंह, चेयरमैन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ ने कहा कि वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना विकास के लिए वैज्ञानिक परीक्षण एवं भू-तकनीकी अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अभियंताओं को आधुनिक तकनीकों एवं नवाचारों को अपनाने तथा तकनीकी उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया।

# एपीएस एकेडमी इंटर कॉलेज के नए परिसर का भव्य उद्घाटन

● .....मोहनलालगंज के मेमोरा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सीबीएसई विद्यालय की नई शाखा शुरू, सांसद दिनेश शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि रहे मौजूद

.....शिक्षा के साथ संस्कारों पर दिया गया विशेष बल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**मोहनलालगंज/ लखनऊ।** मोहनलालगंज क्षेत्र के मेमोरा ग्राम स्थित ढाकेंबीर मंदिर के निकट स्वामी करपात्री राष्ट्रीय गौशाला परिसर में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एपीएस एकेडमी इंटर कॉलेज (सीबीएसई बोर्ड) की नई शाखा का भव्य उद्घाटन शिव-परशुराम कथा एवं उद्घाटन समारोह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कथा व्यास पूज्य स्वामी मुकेश आनंद महाराज ने शिक्षा और संस्कारों के समन्वय का संदेश देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने विद्यार्थियों से ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया।समारोह में विद्यालय परिवार की ओर से शिव प्रकाश मिश्रा 'सेनानी', सिंधुजा मिश्रा, प्रथमेश प्रकाश मिश्रा एवं प्रधानाचार्या प्रीती मिश्रा सेनानी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, विधान परिषद सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह तथा राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पंडित सुनील भरद्वाज ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण, अनुशासन और संस्कारों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। न्यास के ट्रस्टी अध्यक्ष शिव प्रकाश मिश्रा 'सेनानी' एवं प्रधानाचार्या प्रीती मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति का विकास भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में आधुनिक डिजिटल शिक्षण संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने ग्रामीण अंचल में उच्चस्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की इस महत्वपूर्ण पहल की सराहना करते हुए विद्यालय के विशाल परिसर एवं आधुनिक सुविधाओं की प्रशंसा की। कार्यक्रम का समापन संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना एवं क्षेत्र के नागरिकों, शिक्षाविदों तथा अभिभावकों की गरिमामयी उपस्थिति के साथ हुआ।

# अवैध कच्ची शराब के साथ चार आरोपी गिरफ्तार

**लालगंज (रायबरेली)।** कोतवाली पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। एसआई अर्चना की अगुवाई में टिकरान मोड़ के पास से टिकरान गांव निवासी गुड़िया को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। वहीं बहाई के पासिन टोला में शराब बेच रहे फूलचंद को भी पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास से 10 लीटर कच्ची शराब मिली। इसके अलावा नरपतगंज निवासी श्यामू और टिकरान गांव निवासी मायाराम पासी के पास से भी 10-10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। मायाराम को पुलिस टीम ने बछरावां रोड स्थित चांदा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

# सीएचसी की बदहाल सड़क बनी मरीजों के लिए मुसीबत, गड्ढों और जलभराव से परेशानी

● हिचकोले खाते मरीजों को लेकर पहुचती एंबुलेंस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**लालगंज (रायबरेली)।** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परिसर की जर्जर सड़क और धंसी इंटरलॉकिंग मरीजों व तीमारदारों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जगह-जगह सड़क उखड़ चुकी है और बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। हल्की बारिश में भी परिसर में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे मरीजों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीएचसी में प्रतिदिन करीब 500 से 700 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं। गर्मी के मौसम में मरीजों की संख्या और बढ़ जाती है। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन परिसर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। अस्पताल परिसर में मरीजों और तीमारदारों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। गोल चबूतरे के अलावा कोई बेहतर इंतजाम नहीं है। वहीं कई सीमेंट की कुर्सियां भी टूटी पड़ी हैं। आलमपुर रोड से मुख्य भवन तक जाने वाला रास्ता गड्ढों से भरा होने के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और मरीजों को काफी परेशानी होती है। कई लोग फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। वहीं पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े रहते हैं, जिससे इमरजेंसी में पहुंचने वाली एंबुलेंस को भी परेशानी उठानी पड़ती है। आलमपुर निवासी अंकुर, उमाशंकर गुप्ता, रजनू तिवारी और लक्ष्मीशंकर मौर्य सहित अन्य लोगों ने बताया कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर की सड़क दुरुस्त कराने और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की है।


## कार्यालय ग्राम पंचायत रामदासपुर, विकासखण्ड मोहनलालगंज, जनपद- लखनऊ

पत्रांक-मेमो/पंचम वित्त आयोग/पन्द्रहवाँ वित्त आयोग/मनरेगा/ एस0 एल0 डब्लू0 एम0/ सी0 एस0 सी0/आर0 सी0 सी0 सेन्टर/टेंडर/ 2026-2027/ दिनाँक- 17/06/2026

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रामदासपुर वर्ष 2026 - 2027 मे जन सुविधा केन्द्र निर्माण कार्य व ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्लू.एम) एस.बी. एम. -जी के अंतर्गत व्यक्तिगत व सामुदायिक,- कम्पोस्ट पिट, व्यक्तिगत व सामुदायिक नाडेप निर्माण कार्य, सामुदायिक वर्मी कम्पोस्टिंग निर्माण कार्य, सामुदायिक एवं संस्थागत कचरा पात्र, सामुदायिक एवं संस्थागत प्लाटिक बैंक, कचरा वाहन (ई-रिक्शा) स्वच्छता किट, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र निर्माण, सामुदायिक एवं संस्थागत इन्सिनरेटर, व्यक्तिगत व सामुदायिक सोक पिट), आर0सी0सी0 सेन्टर , सिल्ट केचर, फिल्टर चैबर, यू -टाइप नाली निर्माण, भूमिगत नाली निर्माण, पंचायत घर मरम्मत निर्माण कार्य, हैण्डपम्प प्लेटफार्म रेट्रोफिटिंग, हैण्ड पम्प पर सोक पिट निर्माण, सामुदायिक एवं संस्थागत लीच पिट निर्माण, गौ आश्रय केन्द्र निर्माण, विद्यालय कायाकल्प, खड़ंजा निर्माण, खड़ंजा मरम्मत, इंटरलॉकिंग निर्माण, सीसी रोड, नाली निर्माण, नाली मरम्मत, हैंडपंप मरम्मत, रिबोर, ह्यूम पाइप क्रय, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, एवं पंचायत भवन मरम्मत, स्कूल भवन, शौचालय मरम्मत, आँगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन मरम्मत एवं मनरेगा कार्य योजना के सापेक्ष स्वीकृत कार्यों हेतु सामग्री ईट, सीमेंट, बालू, मौरंग, सरिया, आरसीसी, टाइल्स, पत्थर गिट्टी, सिरेमिक टाइल्स, फ्लोरिंग सामग्री, हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर सामग्री आदि सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों से कार्यालय ग्राम पंचायत रामदासपुर पर निविदा दिनांक 25/06/2026 तक समय शाम 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है निविदा उसी दिन शाम 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं गठित क्रय समिति के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जाएगी।

अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

नोट- (1) उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों का सेल्स टैक्स विभाग मे पंजीयन अनिवार्य है।

(2) किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

श्री राजकुमार पाण्डेय
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत- रामदासपुर
विकासखण्ड- मोहनलालगंज
जनपद- लखनऊ

श्री शैलेन्द्र वर्मा
ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत- रामदासपुर
विकासखण्ड- मोहनलालगंज
जनपद- लखनऊ

## कार्यालय ग्राम पंचायत नटौली, विकासखण्ड मोहनलालगंज, जनपद- लखनऊ

पत्रांक-मेमो/पंचम वित्त आयोग/पन्द्रहवाँ वित्त आयोग/मनरेगा/एस0एल0डब्लू0एम0/सी0एस0सी0/आर0सी0सी0 सेन्टर/टेंडर/2026 -2027/ दिनाँक-18/06/2026

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नटौली वर्ष 2026 - 2027 मे जन सुविधा केन्द्र निर्माण कार्य व ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्लू.एम) एस.बी. एम.-जी के अंतर्गत व्यक्तिगत व सामुदायिक,- कम्पोस्ट पिट, व्यक्तिगत व सामुदायिक नाडेप निर्माण कार्य, सामुदायिक वर्मी कम्पोस्टिंग निर्माण कार्य , सामुदायिक एवं संस्थागत कचरा पात्र, सामुदायिक एवं संस्थागत प्लाटिक बैंक, कचरा वाहन (ई-रिक्शा) स्वच्छता किट, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र निर्माण, सामुदायिक एवं संस्थागत इन्सिनरेटर, व्यक्तिगत व सामुदायिक सोक पिट), आर0सी0सी0 सेन्टर, सिल्ट केचर, फिल्टर चैबर, यू -टाइप नाली निर्माण, भूमिगत नाली निर्माण, पंचायत घर मरम्मत निर्माण कार्य, हैण्डपम्प प्लेटफार्म रेट्रोफिटिंग, हैण्ड पम्प पर सोक पिट निर्माण, सामुदायिक एवं संस्थागत लीच पिट निर्माण, गौ आश्रय केन्द्र निर्माण, विद्यालय कायाकल्प, खड़ंजा निर्माण, खड़ंजा मरम्मत, इंटरलॉकिंग निर्माण, सीसी रोड, नाली निर्माण, नाली मरम्मत, हैंडपंप मरम्मत, रिबोर, ह्यूम पाइप क्रय, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, एवं पंचायत भवन मरम्मत, स्कूल भवन, शौचालय मरम्मत, आँगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन मरम्मत एवं मनरेगा कार्य योजना के सापेक्ष स्वीकृत कार्यों हेतु सामग्री ईट, सीमेंट, बालू, मौरंग, सरिया, आरसीसी, टाइल्स, पत्थर गिट्टी, सिरेमिक टाइल्स, फ्लोरिंग सामग्री, हैंडपंप मरम्मत/रिबोर सामग्री आदि सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों से कार्यालय ग्राम पंचायत नटौली पर निविदा दिनांक 25/06/2026 तक समय शाम 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है निविदा उसी दिन शाम 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं गठित क्रय समिति के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जाएगी।

अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

**नोट-** (1) उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मों का सेल्स टैक्स विभाग मे पंजीयन अनिवार्य है।

(2) किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

श्री सुष्पेन्द्र बहादुर सिंह
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत- नटौली
विकासखण्ड- मोहनलालगंज
जनपद- लखनऊ

श्री शैलेन्द्र वर्मा
ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत- नटौली
विकासखण्ड- मोहनलालगंज
जनपद- लखनऊ

# संक्षिप्त खबरें

## असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जुड़े माननीय कोर्ट में पेंडिंग केस के स्टेटस का रिव्यू किया



**नवांशहर-** डिप्टी कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलाख के निर्देशों के अनुसार, असिस्टेंट कमिश्नर (जनरल) रमनजीत ने आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, SDM, तहसील और दूसरे ऑफिस से जुड़े माननीय कोर्ट में पेंडिंग केस के रिव्यू के लिए एक स्पेशल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान, अलग-अलग माननीय कोर्ट में पेंडिंग केस की जांच की गई और केस के मौजूदा स्टेटस के बारे में जानकारी ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ने अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग कोर्ट में जवाब, क्लेम और फाइलें समय पर जमा की जाएं ताकि किसी भी मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कमी न रहे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को माननीय कोर्ट में पेंडिंग केस की सुनवाई के लिए तय तारीखों पर हाज़िरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केस के निपटारे में देरी के कारणों का भी रिव्यू किया गया और भविष्य में ऐसी देरी से बचने के लिए सही इंतज़ाम करने को कहा गया।

## दिल्ली के साकेत में 20 दिन से नलों में आ रहा सीवर जैसा काला पानी

दिल्ली। साकेत के सैदुलाजाब इलाके में पिछले 20 दिनों से लोग दूषित जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि घरों में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से गंदे, बदबूदार और सीवर जैसे काले पानी की आपूर्ति की जा रही है। इससे एक तरफ जहां लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हैं, वहीं दूषित जलापूर्ति से बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। लोगों के मुताबिक इस संबंध में कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सैदुलाजाब गली नंबर-3 के निवासियों के अनुसार पिछले करीब 20 दिनों से गंदा पानी मिल रहा है। पानी में इतनी भीषण बदबू है कि इसे किसी काम में नही लाया जा सकता है। कई बार तो सीवर के जैसा गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। लोगों ने मजबूरन जल बोर्ड की ओर से मिल रहे पानी को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और बाजार से पानी खरीदकर और टैंकर मंगवाकर जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इससे एक तरफ जहां जेब पर भार बढ़ा हुआ है वहीं आए दिन टंकी में गंदा पानी पहुंचने से कई बार उसकी सफाई भी करानी पड़ती है।

## दिल्ली के पॉश इलाके चाणक्यपुरी के एक रेस्तरां में आग, समय रहते टला बड़ा हादसा

**दिल्ली।** चाणक्यपुरी स्थित एक रेस्तरां में बुधवार सुबह आग लग गई। दमकल विभाग को इसकी सूचना सुबह करीब 6:09 बजे मिली, जिसके बाद आनन-फानन में मौके पर पांच गाड़ियों को भेजा गया और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है। अभी तक आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले, मंगलवार दोपहर को उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।

## NOTICE

It is informed to the general public that I, BAHARUL HOQUE CHOUDHURY, Date of Birth-12-03-1978, S/O. Late Abdul Malik Choudhury, a permanent resident of- Vill. Cachar Sugar Mill Colony, P.O. & P.S. Ratabari, Dist. Sribhumi (Karimganj), Assam, I am citizen of India by birth and permanent resident of the above mentioned address. That I am the holder of Passport vide No.E1127307. That my actual and correct name is Baharul Hoque Choudhury. That in my aforesaid Passport my name has been recorded as Mohammed Baharul Hoque Choudhury instead of my actual and correct name Baharul Hoque Choudhury. That both Baharul Hoque Choudhury & Mohammed Baharul Hoque Choudhury are the names of same and one person i.e. my name. That my father's actual & correct name is Abdul Malik Choudhury. That in my aforesaid Passport my father's name has been recorded as Md. Abdul Malik Choudhury instead of Abdul Malik houdhury. That both Abdul Malik Choudhury & Md. Abdul Malik Choudhury are the names of same & one person i.e. my father's name.

# सलमान खान की वजह से हुई गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में शूटर ने उगला सच

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**नई दिल्ली।** पश्चिम विहार में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के '24 ॥श्ह्वह्म्ह्य फिटनेस जिम' के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो शूटरों को बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सोनीपत के रेवारा गांव के अरमान और तुषार उर्फ टाशू उर्फ पिंकू के रूप में हुई है। इन्होंने अमेरिका में बैठे लॉरेंस गिरोह के गैंग्सटर अनिल पंडित के निर्देश पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस दोनों आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और फरार उनके दो साथियों की तलाश में जुटी है। क्राइम ब्रांच के विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल के मुताबिक, 11 जून की सुबह करीब चार बजे पश्चिम विहार में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के '24 Hours फिटनेस जिम' के बाहर फायरिंग की गई थी। जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने जिम पर फायरिंग की। हालांकि इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ था। स्थानीय पुलिस को मौके से सात खाली कारतूस जब्त किए और केस दर्ज कर जांच शुरू की।



**सलमान खान से नजदीकी बढ़ने पर करवाई थी फायरिंग**

बाद में, लॉरेंस गिरोह के अनिल पंडित की एक इंस्टाग्राम पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई। इस पोस्ट में उसने जिम में हुई फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि गुरु रंधावा बालीवुड एक्टर सलमान खान के बहुत करीब आ रहे थे। उसने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहले ही रंधावा को सलमान खान से दूर रहने की चेतावनी दी थी, जिसे वे अपना दुश्मन मानते हैं। आरोपितों को पकड़ने के लिए मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और एसीपी एमेश बर्थवाल की देखरेख में और इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने हमलावरों के भागने के रास्ते का पता लगाया और लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया और दिल्ली और हरियाणा में मुखबिरों से जानकारी जुटा साहिल, सागर, अरमान और तुषार की पहचान की। इसके बाद 15 जून को गुप्त सूचना पर बहादुरगढ़ से अरमान और तुषार को गिरफ्तार कर लिया।

**साहिल और सागर का चचेरा भाई है अरमान**

पूछताछ में पता चला कि अरमान 10वीं तक पढ़ा है और 2022 में पिता की निधन के बाद अपनी मां व बहन के साथ तिलक नगर में रह रहा था। वह शूटर साहिल और सागर का चचेरा भाई है। तुषार 12वीं तक पढ़ा है। उसके माता-पिता ने 2008 में आत्महत्या कर ली थी। वह 2023 में स्टडी वीजा पर रूस गया था और वहां केएफसी में काम करता था। 31 मई को देश लौटने के बाद वह साहिल-सागर के संपर्क में आया और जिम के बाहर फायरिंग की साजिश में शामिल हो गया।

# परिवारिक विवाद में चचेरे भाई के सीने में दागीं 6 गोलियां, दिल्ली के संगम विहार में सुबह-सुबह गूंजीं गोलियां

**दिल्ली।** दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में शिव मंदिर के पीछे 16 नंबर गली में बुधवार सुबह पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 25 वर्षीय चचेरे भाई भूरा की छह राउंड गोलियां दागकर हत्या कर दी गई। आरोपी इंद्रजीत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार, दोनों परिवार आसपास ही रहते हैं और लंबे समय से उनके बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार सुबह विवाद बढ़ गया, जिसके बाद इंद्रजीत ने भूरा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटनास्थल पर ही भूरा की मौत हो गई। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया है कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश थी, जो समय-समय पर झगड़ों में बदल जाती थी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी इंद्रजीत को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।

# 'अल्फा' का ट्रेलर देख याद आए 'धुरंधर' के जमील जमाली, रणवीर की फिल्म को नहीं भूला पाए फैंस; आलिया को किया ट्रोल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालिया रिलीज 'अल्फा' के ट्रेलर को नेटिजंस ने जिस तरह से ट्रोल किया है, वह मेकर्स के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। दरअसल, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स 'अल्फा' की तुलना फिल्म 'धुरंधर' से कर रहे हैं। बता दें कि 'धुरंधर' और 'अल्फा' दोनों ही स्पाई एक्शन फिल्म हैं। जानिए, 'अल्फा' को ट्रोल करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स क्या कह रहे हैं।

**'धुरंधर' के जमील जमाली को बताया बेस्ट स्पाई**

'अल्फा' के ट्रेलर में आलिया भट्ट एक स्पाई के रोल मे हैं। वह एक्शन सीन्स करती दिख रही हैं। लेकिन उनका यह अंदाज दर्शकों को कुछ खास नहीं जमा है। इसके बजाय 'धुरंधर 2' में बिना एक्शन किए ही जमील जमाली ने बेस्ट स्पाई बनकर दिखाया था, यह बात फैंस के जेहन से नहीं उतर रही है। इसी बात को लेकर फैंस 'धुरंधर 2' फिल्म से जमील जमाली के किरदार के सीन सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, इन्हें 'अल्फा' से बेहतर बता रहे हैं। वहीं रणवीर सिंह कई सीन्स को भी दर्शक मास्टरपीस बोल रहे हैं। फैंस 'धुरंधर 2'




की दीवानगी में ऐसे खोए हैं कि उन पर 'अल्फा' के ट्रेलर का कोई असर नहीं हो रहा है।

**अरशद पप्पू जैसे छोटे किरदार भी 'अल्फा' के ट्रेलर पर भारी**

फिल्म 'धुरंधर 2' में अरशद पप्पू नाम का एक छोटा किरदार था, जो ल्यारी का एक बदमाश था। उसके सीन्स को भी फैंस 'अल्फा' के ट्रेलर से बेहतर बता रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स 'अल्फा' के डायलॉग्स का भी मजाक बना रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स 'धुरंधर' के हिट डायलॉग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और 'अल्फा' के डायलॉग्स को बिल्कुल हल्का बता रहे हैं।

फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट, शरवरी के अलावा बॉबी देओल और अनिल कपूर अहम भूमिकाओं में हैं। ट्रेलर में ऋतिक रोशन की झलक भी दर्शकों को मिली है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह फिल्म में कैमियो करेंगे। यह फिल्म 03 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'अल्फा' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है।

# ड्रग-फ्री इंडिया कैंपेन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को शपथ दिलाई

**● एडमिनिस्ट्रेशन ने 16 से 26 जून तक ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल कैंपेन शुरू किया**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**शहीद भगत सिंह नगर-** ड्रग-फ्री इंडिया कैंपेन के तहत, शहीद भगत सिंह नगर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अहम पहल की है। इस कैंपेन के तहत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) संजीव शर्मा की लीडरशिप में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्रग्स के खिलाफ डटकर खड़े होने और समाज को ड्रग-फ्री बनाने की शपथ दिलाई गई। यह कैंपेन पंजाब सरकार के सोशल सिक्योरिटी, महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट की कोशिशों से चलाया जा रहा है।्ररू्रष्ट संजीव शर्मा ने कहा कि ड्रग-फ्री इंडिया कैंपेन के तहत लगातार अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। इस बार 16 जून से 26 जून तक एक स्पेशल एक्शन प्रोग्राम बनाया गया है,



जिसमें ऑनलाइन मास प्लेज कैंपेन, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और निबंध कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज़ किए जाएंगे। इस कैंपेन का मुख्य मकसद युवाओं को ड्रग्स के दलदल से निकालकर स्पोर्ट्स और दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की ओर मोटिवेट करना है। ये सभी एक्टिविटीज़ कॉलेज और अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव लेवल पर की जाएंगी ताकि डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से ड्रग फ्री बनाया जा सके। इस दौरान अलग-अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर मौजूद थे।

# रेड फोर्ट आतंकी हमला: अलफलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी ने मांगी बेल




**दिल्ली।** दिल्ली हाई कोर्ट ने रेड फोर्ट आतंकी हमले के आरोपी और अलफलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका पर एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) से जवाब मांगा है। सिद्दीकी ने अपनी पत्नी के कैंसर इलाज के आधार पर जमानत की मांग की है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। जवाद अहमद सिद्दीकी पर रेड फोर्ट पर हुए आतंकी हमले के मामले में संलिप्तता का आरोप है। सिद्दीकी लंबे समय से जेल में हैं।

# कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने अलग-अलग गांवों के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपये जारी किए

**● BDPO ऑफिस में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कमेटी मेंबर के साथ खास मीटिंग**

**पंजाब सरकार गांवों के हर तरह के विकास के लिए पूरी तरह तैयार**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**होशियारपुर-** पंजाब सरकार की तरफ से गांवों के हर तरह के विकास और लोगों को बेहतर बेसिक सुविधाएं देने के मकसद से पंजाब के जेल और ह्रक्रढ्ढ मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज लोकल BDPO ऑफिस में एक खास मीटिंग की, जिसमें कहा कि पंजाब सरकार गांवों की सूरत बदलने के लिए बड़े कदम उठा रही है। मीटिंग के दौरान, ब्लॉक-1 के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सभी कमेटी मेंबर से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने ब्लॉक के तहत अलग-अलग गांवों में चल रहे विकास कामों का रिव्यू किया। कैबिनेट मंत्री ने भविष्य में किए जाने वाले विकास प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में चर्चा की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने ब्लॉक-1 के अलग-अलग गांवों के विकास कामों में और तेजी लाने के लिए पंचायतों को 1.50 करोड़ रुपये की रकम जारी की है। उन्होंने कहा कि इन फंड का इस्तेमाल गांवों में सड़कें, गलियां, नालियां, पीने का साफ पानी, स्ट्रीट लाइट और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार गांवों के विकास को पूरी प्राथमिकता दे रही है।

सरकार का मकसद गांवों को हर तरह से मजबूत और विकसित बनाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले भी कई ऐतिहासिक विकास के फैसले लिए हैं, जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों और समिति सदस्यों के साथ मीटिंग करके विकास कामों का रिव्यू करने का मकसद गांवों की समस्याओं को गहराई से जानना और उनका जल्द से जल्द समाधान पक्का करना है। मीटिंग के दौरान मौजूद कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों ने भी पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया और कहा कि



सरकार गांवों के विकास के लिए रिकॉर्ड लेवल पर फंड जारी कर रही है, जिससे विकास कामों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई के लिए समर्पित सरकार की नीतियों की वजह से गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है और लोगों की लंबे समय से पेंडिंग मांगें पूरी हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से विकास के कामों की क्वालिटी पक्का करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार आने वाले समय में भी गांवों के विकास के लिए इसी तरह कोशिश करती रहेगी और हर सेक्टर का चौतरफा विकास पक्का किया जाएगा। कैप्शन - पंजाब जेल और NRI मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह B.D., P.O. ऑफिस में प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करते हुए।

# PCS ऑफिसर पूनम सिंह ने मानसा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) का चार्ज संभाला

**● 2014 बैच की अनुभवी ऑफिसर ने मानसा, बठिंडा और लुधियाना में अहम एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर काम किया है**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**मानसा-** अमृत पाल सिद्धू और गौरव सिद्धू द्वारा सीनियर पंजाब सिविल सर्विसेज़ (PCS) ऑफिसर पूनम सिंह, जो 2014 बैच की एक जानी-मानी सदस्य हैं, ने ऑफिशियली मानसा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) का पद संभाल लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव और साबित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, सिंह जिले में डायनैमिक लीडरशिप लाने के लिए तैयार हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूनम सिंह के करियर में कई बड़े जिलों में अहम काम किए गए हैं। इस रोल से पहले, उन्होंने मानसा जिले के सरदूलगढ़ सबडिवीजन में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के तौर पर काम किया, जहाँ उन्होंने सरकारी पहलों को लागू करने और स्थानीय चिंताओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा, पूनम सिंह ने मानसा में असिस्टेंट कमिश्नर का पद भी संभाला है, जिससे जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के बारे में उनकी समझ और मजबूत हुई है। उनके प्रोफेशनल सफर में बठिंडा और लुधियाना में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के तौर पर भी खास समय शामिल है, जहाँ उन्होंने कई ज़रूरी ज़िम्मेदारियाँ निभाईं। इन भूमिकाओं में उनकी लीडरशिप की खासियत असरदार गवर्नेंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने पर फोकस थी। ऑफिस संभालने के बाद,क्क्र सिद्धू से बात करते हुए, सिंह ने मानसा के डेवलपमेंट के लिए अपना विज़न बताया। उन्होंने चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और अलग-अलग सरकारी वेलफेयर स्कीम्स को असरदार तरीके से लागू करने के अपने कमिटमेंट पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, 'मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जिले के पूरे डेवलपमेंट के लिए काम करना है, साथ ही लोगों की शिकायतों को तुरंत दूर करना है।' सिंह ने



ट्रांसपेरेंट और लोगों पर केंद्रित गवर्नेंस के महत्व पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने यह पक्का करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करने का वादा किया कि एडमिनिस्ट्रेशन नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव बना रहे। उन्होंने आगे कहा, 'लोगों की समस्याओं को हल करना और अच्छा गवर्नेंस देना हमारी कोशिशों का मुख्य हिस्सा होगा।' एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) के तौर पर पूनम सिंह की नियुक्ति से मानसा की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में नया फोकस और एनर्जी आने की उम्मीद है। उनके बहुत ज़्यादा अनुभव और पब्लिक सर्विस के प्रति लगन से पॉजिटिव बदलाव आने और जिले की पूरी तरक्की में योगदान मिलने की उम्मीद है।

# विद्यासागर कॉलेज की एनएसएस इकाई का 'दाना-पानी अभियान', पक्षियों के संरक्षण का दिया संदेश

**● भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए आगे आए छात्र, अभियान से जगाई संवेदनशीलता**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गर्मी के मौसम में पक्षियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा 'दाना-पानी अभियान' का आयोजन किया गया। अभियान के तहत कॉलेज परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों के लिए दाना और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में कॉलेज के निदेशक डॉ. बिजय कुमार झा, यूथक्रिया ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक एवं गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष राघब चंद्र नाथ, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रंगलाल बिस्वास, शिक्षक मोहम्मद नासिर उद्दीन तथा एनएसएस स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर डॉ. झा ने कहा कि भीषण गर्मी के दौरान पक्षियों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समाज के छोटे-छोटे प्रयास भी उनके जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राघब चंद्र नाथ ने विद्यार्थियों एवं आम





नागरिकों से अपने घरों, छतों और बालकनियों में मिट्टी के बर्तनों में पानी तथा दाना रखने की अपील की। उन्होंने कहा, 'जीव दया ही सच्चा धर्म है। पक्षियों का संरक्षण कर हम प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं।' अभियान के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों ने मिट्टी की परातों और कुल्हड़ों में पानी भरकर कॉलेज परिसर के विभिन्न स्थानों पर रखा तथा लोगों को भी पक्षियों के प्रति संवेदनशील होकर ऐसे प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार की सामाजिक एवं पर्यावरणीय गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में सेवा, संवेदनशीलता और प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित की जा रही है।

# दिल्ली के डीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री ने किया सिटिजन लाउंज और लर्निंग सेंटर का उद्घाटन

**दिल्ली।** मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय परिसर में नवनिर्मित सिटिजन लाउंज-कम-न्यू एज लर्निंग सेंटर और आधुनिक शौचालय ब्लाक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आधुनिक सिटिजन लाउंज, लाइब्रेरी एवं रीडिंग कार्नर का भी अवलोकन किया। उन्होंने इस पहल को सुशासन और जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक, सुविधाजनक और सकारात्मक अनुभव मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का अर्थ केवल योजनाओं तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि नागरिकों को सहज सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह परिसर केवल एक वेटिंग लाउंज या लाइब्रेरी नहीं, बल्कि नई सोच और बेहतर प्रशासन का एक बड़ा प्रतीक भी है। यहां आसपास की बस्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के बच्चे भी आकर आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। इसे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एक बड़े ज्ञान एवं कौशल विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां कानून, प्रशासन, करियर मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर भी स्थापित किए गए हैं।

# सीलापथार के 15वीं राष्ट्रीय राजमार के विद्युतपृष्ठ होकर एक बुजुर्ग की मौत



**धेमाजी असम।** आज संध्या करीब 7बजे सिलापथार से सिलागांव के राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर बिजली का झटका लगने से एक आदमी की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान 1नंबर सिलागांव के 58 साल के गणेश दास के रूप में हुई है। घटना उस समय हुआ जब गणेश ने रस्ते पार करते समय स्ट्रीट लाइट के खंभे को स्पर्श करते ही विद्युतपृष्ठ हखर मौत हो गई। लोग अब सवाल उठ रहे हैं कि गलती किसकी थी। बिजली विभाग की या सड़क बनाने वाली कंपनी की? हमेशा व्यस्त रहने वाली जगह पर कई स्कूल हैं,यहां स्कूल के छात्रों और आम लोगों का आना-जाना लगा रहता है। पीड़ित की मृत देह सिलापथार पुलिस ने को मौके से बरामद कर ली गई है लेकिन असली राज पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा।

# 'ट्रंप से तीन भारतीयों की हत्या पर बात करें मोदी', केजरीवाल का केंद्र पर हमला; नीट पेपर लीक पर भी घेरा

**● केजरीवाल ने होर्मुज जहाज हमले में भारतीयों की मौत पर पीएम मोदी से ट्रंप के सामने नाराजगी जताने की अपील की है। उन्होंने नीट पेपर लीक और टेलीग्राम प्रतिबंध पर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि पेपर लीक का धंधा अरबों का है।**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**दिल्ली।** होर्मुज में जहाज पर हुए हमले में तीन भारतीयों की हत्या पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमलावर हैं। केजरीवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने तीन भारतीयों की हत्या को लेकर कड़ी नाराजगी जताने की प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक वीडियो संदेश एक्स पर साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री फ्रांस में ट्रंप से मिल रहे हैं, केजरीवाल ने




उम्मीद जताई कि तीन भारतीयों की हत्या पर भारत का सख्त विरोध और गुस्सा उन तक पहुंचाएंगे।

**टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने पर उठाए सवाल**

वहीं, केजरीवाल केजरीवाल ने नीट परीक्षा को लेकर 22 जून तक टेलीग्राम एप पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगाने को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयत ही नहीं है। इसलिए इस तरह के बेतुके कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहरा कि सेना के जहाज़ों से पेपर ट्रांसपोर्ट करने और टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक होना नहीं रुकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक का धंधा अरबों का है, पैसा टाप तक जाता है। उन्होंने तंज कसा कि पेपर लीक बंद कर दिए तो एमएलए और एमपी खरीदने के पैसे कहां से आएंगे।

# इटली: सोशल मीडिया ने ले ली 12 साल की बच्ची की जान

**● माता-पिता ने Meta और Tiktok पर ठोका मुकदमा**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

**रोम।** इटली की 12 साल की रोसेला रोजेरो उगुएस की जिंदगी सोशल मीडिया एल्गोरिदम की गिरफ्त में आकर खत्म हो गई। उसकी मां आइरीन ने बताया कि बेटी के व्यवहार में अचानक बदलाव आया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार उसे खुद को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट दिखा रहा था, जिसके बाद रोसेला ने आत्महत्या कर ली।

**फेक अकाउंट से डिप्रेशन का शिकार**

रोसेला की मौत के बाद माता-पिता ने जब उसका मोबाइल और लैपटॉप खोला तो पता चला कि वह जितना सोचते थे, रोसेला उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही थी। उसने 'Just a dead persOn' नाम से फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, जिसके यूजर नेम में 'O' की जगह '0' (जीरो) का इस्तेमाल किया गया था। सितंबर 2023 में डिप्रेशन से जुड़े कंटेंट देखना शुरू करने के बाद महज पांच महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। उत्तरी इटली के एस्टी शहर में रॉयटर्स से बात करते हुए आइरीन ने कहा, 'एक समय लगा जैसे यह सब अपने आप बढ़ता जा रहा हो। उसने उसकी खुशमिजाज और मिलनसार व्यक्तित्व को पूरी तरह दबा दिया।' उन्होंने इसे अचानक आई विनाशकारी बीमारी की तरह बताया।

**माता-पिता का ने किया केस**

रोसेला के माता-पिता उन कई परिवारों में शामिल हैं जिन्होंने इटली में पहली बार इंस्टाग्राम-फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा और टिकटॉक के खिलाफ सामूहिक मुकदमा दायर किया है। परिवार नाबालिगों की पहुंच पर सख्त पाबंदी और जोखिमों के प्रति जागरूकता की मांग कर रहे हैं। मेटा के प्रवक्ता ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कंपनी टीन अकाउंट्स और सुरक्षा उपायों के जरिए किशोरों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। टिकटॉक ने भी दावा किया कि वह 99 प्रतिशत से ज्यादा हानिकारक कंटेंट हटा देता है और सुरक्षा में निवेश जारी रखे हुए है।

**यूरोप में बढ़ती चिंता**

पूरे यूरोप में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जांच तेज हो रही है। ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने की योजना बनाई है।

यूरोपीय संघ डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत सोशल में मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दबाव बना रहा है। वकील स्टेफानो कोमोडो ने कहा, 'मकसद सोशल मीडिया के फायदों को नकारना नहीं, बल्कि सबसे कमजोर यूजर्स के लिए नुकसानदेह तकनीकी और मार्केटिंग तरीकों को हटाना है।' माता-पिता का कहना है कि प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा व्यवस्था काफी नहीं है। बच्चे आसानी से फिल्टर बायपास कर लेते हैं।